भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 1446
13.02.2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के तहत शीतागार और आपूर्ति शृंखला अवसरंचना

1446. डॉ. भोला सिंह:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) से किसानों को अधिक मूल्य प्राप्ति, कृषि क्षेत्र में लाभ और फसल कटाई के बाद होने वाली हानि में कमी के संदर्भ में किस प्रकार लाभ हुआ है;
- (ख) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विशेषकर अपशिष्ट में कमी, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनता में सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है/ की जा रही है;
- (ग) क्या पीएमकेएसवाई के अंतर्गत शीतागारों और आपूर्ति शृंखला अवसरंचना में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कोई नई योजनाएं/वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किए जा रहे हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात का विस्तार करने और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)**

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना - पीएमकेएसवाई को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य फसल-उपरांत बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करना है, ताकि फसल-उपरांत नुकसानों में कमी लाने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पीएमकेएसवाई के तहत घटक योजनाएं उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसल-उपरांत नुकसानों को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतित वाहन शामिल हैं।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बुनियादी ढांचे के निर्माण, बिक्री आधारित प्रोत्साहनों के अनुदान, क्षमता विस्तार और अन्य सहायक उपायों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जल और वायु के संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड/एजेंसी द्वारा जारी संचालन की सहमति (सीटीओ) अनुमोदित परियोजनाओं को अनुदान सहायता/सब्सिडी की किस्त जारी करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को नॉन-ओडीएस (गैर-ओजोन क्षयकारी पदार्थ) और कम जीडब्ल्यूपी (कम ग्लोबल

वार्मिंग क्षमता) रेफ्रिजरेंट्स-आधारित ऊर्जा कुशल शीतलन प्रणालियों के उपयोग के संबंध में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कोल्ड चैन बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं के तहत, परियोजना के लिए नवीकरणीय/वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर, बायोमास, पवन, आदि) के लिए भी सहायता प्राप्त की जा सकती है (अधिकतम पात्र अनुमेय लागत प्रति परियोजना 35 लाख रुपये है)। देश भर से पात्र संस्थाएँ आवेदन कर सकती हैं और लाभ उठा सकती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान - तंजावुर ने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, पॉली लैक्टिक एसिड (पीएलए), स्टार्च, नैनो फाइबर आदि जैसे बायोपॉलिमर से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग समाधान के विकास के माध्यम से टिकाऊ पैकेजिंग प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और विकसित करने के प्रयास किए हैं।

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन के माध्यम से देश भर में खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है। यह योजना न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि अन्य बातों के अलावा, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) को भी लागू कर रहा है। वैश्विक खाद्य चैंपियन बनाने और विदेशों में भारतीय खाद्य ब्रांडों की दृश्यता में सुधार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई है।

इसके अलावा, संबद्ध मंत्रालय/विभाग और उनकी एजेंसियां जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, एपीडा, एमपीडा आदि भी अपनी संबंधित योजनाओं जैसे एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि निर्यात संवर्धन योजना, राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा आदि के माध्यम से समर्थन प्रदान करते हैं।

कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात क्षेत्र की मदद के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण योजना के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा निर्यातकों को वित्तीय सहायता, इन-हाउस गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना और प्रसंस्करण इकाइयों में जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं (एचएसीसीपी) का कार्यान्वयन, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली पर जागरूकता कार्यक्रम और खाद्य सुरक्षा मानदंडों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, विभिन्न खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए पैकेजिंग विकसित करना और विभिन्न राज्यों में भौगोलिक दृष्टि से सटे क्षेत्रों में कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत आईएसओ 9000, एचएसीसीपी आदि सहित कुल गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन और देश में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।